साथ-साथ अन्य स्थानों पर भी चौकसी करने के लिए तैनात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस सुरक्षा बल की संख्या/कार्यक्षमता घटती जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने देश की सुरक्षा की आवश्यकतानुसार उपर्युक्त अर्धसैनिक बल की संख्या व क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आन्तरिक सुरक्षा की ड्यूटियों के लिए भी सीमा सुरक्षा बल को आंशिक रूप से तैनात किया गया है परन्तु तैनाती तर्कसंगतपूर्ण ढंग से इस प्रकार की जाती है जिससे कि सीमाओं की सुरक्षा प्रभावित न हो।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में पुलिस कार्मिकों की संख्या

841. **श्री राम जेठमलानी**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य की जनसंख्या को देखते हुए यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए पुलिस की वर्तमान संख्या पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो अभी कितने पुलिस बल आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है;

(ग) क्या इस पुलिस बल पर व्यय होने वाली राशि का भी अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी तथा इसे प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किन-किन स्त्रोतों का पता लगाया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार): (क) से (घ) सरकार को खासकर, आबादी में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए दिल्ली पुलिस की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता की जानकारी है। बल की संख्या में वृद्धि किया जाना एक सतत प्रक्रिया है तथा यह कार्य निधियों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

Private Detective Agencies

842. SHRI KULDIP NAYYAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is a system of licensing with appropriate statutory backing to control the working of private detective agencies which have come up in the country in the recent years;

(b) how many such agencies are operating in the country and in which States; and

(c) whether these agencies are financed and controlled purely by India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (c) As 'Police' and 'Public Order' are included in the State List of the VII Schedule to the Constitution of India, licensing and controlling the functioning of private detective agencies primarily fall under the purview of the State Governments. Information on the number of detective agencies is not centrally maintained.

Political Dialogue for Solving Insurgency in Assam

843. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) as follow-up of ministerial declarations that the problem of insurgency in Assam cannot be solved by army operations but calls for political dialogue, the measures, the authorities intend to pursue to initiate such a dialogue;

(b) whether it is Government's intention to announce a general amnesty as a prelude to the commencement of the political dialogue; and

(c) whether there is any proposal to reveal to the public the nature of foreign involvement contributing to the instability in Assam?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) the Prime Minister has made an open invitation to any group of individuals including militants without any precondition to meet him and discuss their legitimage grievances. But no militant organisation in Assam has so far responded.